



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—हण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्रार्थकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. ६३८]

नहीं दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 9, 1989/आस्त्रिवं 17, 1911

No. 638]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 9, 1989/ASVINA 17, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संक्षेप के रूप में रचा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कुपि और सहकारिता विभाग)

ग्राहेश

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 1989.

का.मा. 796 (प्र) : बहुराज्य सहकारी सोसाइटी प्रधिनियम, 1984 (1984 का 51) की, जिसे इसमें इस हेतु प्रवातु "प्रधिनियम" कहा गया है, आरा 49 को उपचारा (1) में यह उपबंध है कि जहाँ किसी वदुराज्य सहकारी सोसाइटी के नियेक बोर्ड का प्रधिकरण किया जाता है वहाँ केन्द्रीय रजिस्ट्रार एक या प्रधिक प्रशासकों को सोसाइटी के लायनियां का एक वर्ष से प्रधान का देसो प्रधान बैठित, जो प्रवृत्ति केन्द्रीय रजिस्ट्रार

के विवेक पर, समय-समय पर बढ़ाई जा सकती, किन्तु जिसकी कुल अवधि वो वर्ष से अधिक नहीं होगी, प्रबंध करने के लिए नियुक्त कर सकते :

और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली की बाबत किसी प्रशासक की नियुक्ति के लिए, दो वर्ष भी उक्स अवधि 14 अक्टूबर, 1989 को समाप्त होगी:

और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के पुनर्वास के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाए गए ऐसे एकमुख अधिकारों के परिणामस्वरूप जो कार्यान्वयित किए जा चुके हैं, हानियों में पर्याप्त कमी दुर्बल है, अलाभकर शाखाएं बंद हो गई हैं, प्रशासन अधिकारों से शोषणों की वसूली हुई है, वित्तीय और वाणिज्यिक कामकाज बेहतर सूझा है और नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के कार्यकरण में व्यापक सुधार हुआ है:

और अधिकारिग की दो वर्ष की अवधि की समाप्ति पर नए घोड़े के गठन के लिए प्रारंभ 48 की उपचारा (4) अधीन कार्यवाई से, विशेषज्ञ समिति को सिकारिशों के परिणामस्वरूप प्रारंभ किये जाने पुनर्वास के क्रम के कार्यान्वयन की गति से धीमे पड़ने की संभावना है:

और नागरिक पूर्ति विभाग ने, जो नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के लिए प्रशासनिक विभाग है, 14 अक्टूबर, 1989 के पूरे एक वर्ष की और अवधि, के लिए प्रशासन को बनाए रखने की सिफारिश की है:

अतः इब, केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की घारा 99 की उपचारा (2) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली को अधिनियम की घारा 48 की उपचारा (1) के उपर्योग से उस सीमा तक छूट देती है जिस तक प्रशासक नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्यकारीयों का 30 जून, 1990 तक की और अवधि के लिए प्रबंध करेगा ।

[सं. एल--11011/11/89-एल व एम]
जे.एन.एस. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

ORDER

New Delhi, the 9th October, 1989

S.O. 796(E).—WHEREAS sub-section (1) of section 48 of the Multi-State Co-operative Societies Act, 1984 (51 of 1984) hereinafter referred to as the 'Act' provides that where the Board of Directors of a multi-State co-operative society is superseded, the Central Registrar may appoint one or more administrators to manage the affairs of the society for such period not exceeding one year which period may, at the discretion of the Central Registrar, be extended from time to time, so, however, that the aggregate period does not exceed two years;

AND WHEREAS the said period of two years for the appointment of an administrator in respect of National Co-operative Consumers Federation of India Limited, New Delhi will expire on the 14th October, 1989;

AND WHEREAS the package of measures suggested by the Expert Committee for rehabilitation of the National Co-operative Consumers Federation of India Limited, Which are since being implemented, have resulted in substantial reduction of losses closure of uneconomic branches, recovery of dues from the sundry debtors, better financial and commercial management and overall improvement in the working of the National Co-operative Consumers Fcderation of India Limited ;

AND WHEREAS action under sub-section(4) of section 48 for constituting a new board on the expiry of two years period of supersession is likely to retard the pace of implementation of the rehabilitation programme initiated as a result of the recommendations of the Expert Committee ;

AND WHEREAS the Department of Civil Supplies, the administrative Department for the National Co-operative Consumers Fcderation of India Limited, has recommended the continuation of the administrator for a further period of one year beyond the 14th October, 1989.

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 99 of the Act, the Central Government hereby exempts the National Co-operative Consumers Federation of India Limited, New Delhi, from the provisions of sub-section (1) of section 48 of the Act to the extent that the administrator will manage the affairs of the National Co-operative Consumers Federation for a further period upto the 30th June, 1990.

[No. L-11011/11/89-L&M]
J. N. L. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

